ultimately the foreign investor gets will be utilised for the Indian economy itself?

Shri F. A. Ahmed: So far as the question of foreign exchange is concerned, the hon. Member must bear in mind that we only allow such foreign exchange to come in with respect to capital equipment which is not available in our country, and which we require immediately for the purpose of development, and only in those cases the question of foreign exchange is taken into consideration And whenever these agreements are entered into, we try to safeguard the interests of the country so that as much as possible the profits earned here do not go out of our country

Shri S. S. Kothari: Is the investment climate considered satisfactory by the Government? How does the return on capital invested in this country compare with the return on capital invested in other countries?

Mr. Speaker: Wider, much wider question

Shri F. A. Ahmed It is a question of opinion

Shri Umanath: They have the assessment. In fact, so many times it has been mentioned. The highest return is in this country.

Shri F. A. Ahmed: What I am pointing out is that it is a matter of opinion. That is a question which the investor has to consider and not myself.

Shri Umanath: You have not considered it, the Government has not considered it?

Shri Hem Barua: May I know if it is a fact that the hon. Minister has decided to invite foreign capital, of course from some East European countries, for the purpose of setting up a plant in this country to manufacture small cars? If he has done so, I would like to know.

Mr. Speaker: How does it arise here?

Shri Gopalan: It has been reported that the rate of profit earned from British and American investment in India is the highest in the world as compared to the rate of profit earned in other countries. In view of this, may I now from the Minister what steps they are proposing to take to check this drain of national wealth?

Shri F. A. Ahmed: We examined all these proposals and we find that the agreements are in our favour; then only they are accepted. We do not in every case know what profit is earned by them in other countries and perhaps in many countries the profits earned is less or more than what they are getting in India. . . . (*Interruptions*)

Mr. Speaker: Next question—544.

Incentives for Small-Scale Sector

+

*544. **Shri Sharda Nand:**
Shri Bharat Singh Chauhan:
Shri Ranjit Singh:
Shri N. R. Laskar:
Shri Sradhakar Supakar:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri Shri Gopal Saboo:
Shri A. B. Vajpayee:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Parkash Vir Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to give incentives and facilities to small scale sector in order to hold the price line of consumer goods and to compete in foreign markets;

(b) whether Government have set apart 50 to 60 items of manufacture exclusively for the small scale sector; and

(c) if so, the main features of the proposals and the number of small

scale units in the country which are manufacturing these items?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) Government are already giving incentive and facilities to the small scale sector to increase production. Such incentive and facilities will be increased to the extent possible. Government have last year liberalised imports of raw materials and special facilities were given to the small scale sector in this regard. These are expected to increase production of consumer goods and also help exports.

(b) Government have announced a list of 47 industries reserved exclusively for development in the small scale sector.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No* LT-686/67].

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उन्होंने लाइसेंसेज के लिए अप्रैल 1967 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि निर्धारित कर दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस अवधि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह पालिसी हर साल के लिए डिक्लेयर की जाती है। जब नया साल आयेगा तो उस वक्त इस बारे में सोचा जायगा।

श्री शारदानन्द : क्या सरकार इन छोटे पैमाने के उद्योगों को ऐक्साइज ड्यूटी तथा सेल्स टैक्स आदि करों के संबंध में कुछ राहत देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह तो जरा एक मुश्किल सवाल है। हर एक चीज को सोचा जायगा और फाइनेंस मिनिस्टर उस को देखेंगे कि किन चीजों पर टैक्स कम किया जा सकता है ?

श्री भरत सिंह चौहान : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्मौल स्केल इन्डस्ट्रीज का क्या कोई पैमाना है कि कितनी यह स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज प्राइवेट सैक्टर में की जायेंगी और किस ढंग की की जायेंगी ? कोई इस प्रकार का क्या विचार किया गया है क्योंकि जहां तक प्रोत्साहन या इन्सैंटिव देने का प्रश्न है प्राइवेट सैक्टर में यह भी बड़ी शंका है कि सरकार कौन सी नीति अख्तयार कर सकती है उन के बिजनैस को खत्म करने के लिए। इसलिए यह एक तरीके की प्राइवेट सैक्टर में जो पूंजी पड़ी हुई है देश में अरबों रुपये की वह आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या इस पर सरकार ने विचार किया है कि यह अरबों की जो पूंजी पड़ी हुई है उस का उपयोग उन को गारन्टी देकर किया जा सकता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि यहां बतलाया गया है जहां तक स्मौल स्केल इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है 47 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ उनके बनाने के वास्ते रिजर्व कर रक्खी है और अगर इस में ज्यादा की जरूरत हो और उस लिस्ट को और बढ़ाने की जरूरत होगी तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

जहां तक दूसरी सहूलियत का ताल्लुक है, उन को लोन देने का ताल्लुक है, गवर्नमेंट से मदद देने का ताल्लुक है या उन को टैक्निकल एडवाइस देने का ताल्लुक है उस में बहुत हद तक फैसिलिटीज बढ़ा दी गई हैं और जो उन लोगों को दिक्कत हुआ करती थी रॉ मैटीरियल्स और कम्पोनेंट्स पार्ट्स बाहर से लाने के लिए वह भी कुछ दिक्कतें हटा दी गई हैं और मेरा ख्याल है कि स्मौल स्केल इन्डस्ट्रीज काफी आगे बढ़ सकती हैं और काफी प्राईवेट इंटरप्राइज में हिस्सा ले सकती हैं।

Shri Sradhakar Supakar: May I know whether the reduction of period for application of licence for only one year is an experimental measure? May I also know whether on account

of the rejection of these applications, the want of competition in the small sector has not led to the increase in prices of the manufactured goods?

Shri F. A. Ahmed: The policy with regard to the licences is that they are issued from year to year,—the financial year. Last year also we had adopted more or less the same policy from the month of July. This year, after the financial year was over, we have declared our policy for the next year, and there is no reason for us to feel that this policy will be changed when it is really helping the small scale industries people.

So far as competition is concerned, we have not stood in the way and we allow free competition among them, which can certainly bring down the price so far as the consumer is concerned.

श्री कंवर लाल गुप्त: मंत्री महोदय ने जो कहा है कि वह स्माल स्केल सैक्टर के अन्दर इन्सेंटिव देंगे, फ़ैसिलिटी देंगे, उस के संबंध मे मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली कितनी फैसिलिटी एक्स्चेंज के बारे मे, टैकनिकल नो-हाऊ के बारे में और लोन आदि के बारे मे दी है, और क्या स्माल स्केल सैक्टर ने उन के पास अपनी कुछ मागें रक्खी हैं कि यह यह फेसिलिटीज उन को दी जानी चाहिये? यदि रक्खी हैं तो उन के ऊपर मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जहां तक फारेन एक्सचेंज का सवाल है, जहां एप्रोक्समेटली 6 करोड़ की फैसिलिटी मिलती थी वह अब गालिबन 80 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, खासकर उन इलाकों मे जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। वहां हम ने ऐसे टैकनीशियन्स वगैरह रख दिये हैं जो जा कर इंडस्ट्रीज को इन्स्पेक्ट करते हैं, उन से जाकर पूछते हैं कि क्या जरूरत है, और अगर कोई कमी देखते हैं तो वह जा कर अपनी सलाह भी देते हैं। जो कुछ मैं ने खुद दो एक जगहों में देखा उस से मुझे मालूम होता है कि जहां तक टैकनिकल एसिस्टेंस देने का सवाल है उस मे और भी बढ़ाने की गुंजाइश है और हम सोच रहे हैं कि कैसे इस कमी को दूर करें ताकि लेटेस्ट टैकनिकल नो हाऊ मिल सके और वह अपनी इन्डस्ट्रीज को लगा कर उन को और ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा सकें।

श्री कंवर लाल गुप्त: मेरे सवाल का दूसरा भाग यह था कि क्या कोई रिप्रेजेन्टेशन उन का आया है और आया है तो उन्होंने क्या क्या मांगें की हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: उन के रिप्रेजेन्टेशन मे तो बहुत सी बातें हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि वह कहते हैं कि उन को बैंकों से सहूलियत से रुपया नहीं मिलता जैसे कि और इंडस्ट्रीज को मिलता है। स्टेट बैंक से तो रुपया मिलता है लेकिन जो और शेड्यल्ड बैंक्स हैं वह ज्यादा सूद पर रुपया देते हैं इस मे भी उन को दिक्कत है और इस सवाल पर गौर किया जा रहा है।

श्री रामावतार शर्मा: मंत्री महोदय प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक क्या प्रोत्साहन दिया गया है और आगे क्या देने का उन का विचार है? इस प्रोत्साहन के देने में जिन इंडस्ट्रीज का उल्लेख किया जा रहा है उन के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि ग्वालियर क्षेत्र में भी क्या कोई इंडस्ट्री है जिस को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैं ने कहा कि जहां तक इम्पोर्ट का सवाल था, पहले इंडस्ट्रीज को बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब हम ने यह पालिसी अख्तयार की है कि जो 59 प्रायारिटी इंडस्ट्रीज हैं वह 1964-65 मे जितना इम्पोर्ट करती थी उस से तिगुने इम्पोर्ट के लिये लाइसेंस दिये जा रहे हैं, और जो उस के बाद नई आई हैं उन को उस से ज्यादा मिकदार में इम्पोर्ट लाइसेंस वगैरह दिये जा रहे हैं। थोड़ी उन

को टैकनीशियन्स वगैरह की मदद दी जाती है। उन को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलती है, फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से मदद मिलती है। बैंक्स वगैरह जो एड मिलने का सवाल है, हमारी यह कोशिश है कि स्टेट बैंक से और जो शिड्यूल्ड बैंक हैं उन से वह रुपया कर्ज ले सकें किसी तरीके से और उन को सस्ते रेट पर बिजली वगैरह मिले। इन सब बातों की कोशिश की जा रही है और बहुत से इलाकों में उन को इस तरह की मदद मिली है। जहां तक ग्वालियर का सवाल है, जरूर वहां भी कोई न कोई इंडस्ट्रीज हैं लेकिन मेरे पास उन के डिटेल्स नहीं हैं जिस से कि मैं बतला सकूं कि क्या क्या फैसिलिटीस वहां पर दी गई हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि ग्वालियर में इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन उन के पास ब्योरा नहीं है। मैं आप के द्वारा उन को बतलाना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन उद्योगों को प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, वहां जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उन को पूरी तरह से बिजली भी उपलब्ध नहीं है जिस से कि उन को बड़ी दिक्कत हो रही है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : छोटे उद्योगों के रूप में चिर काल से जो पेन्ट्स और वार्निश बनती थी उस पर पहली बार 1956 में एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने अपने सुझाव सामने रक्खे इसलिए वह ड्यूटी माफ कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर 15 मई से फिर से एक्साइज ड्यूटी लगाने का निर्णय सरकार ने किया है? अगर किया है तो क्यों और उस में कौन सा प्रोत्साहन इस उद्योग को मिलेगा?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सवाल तो फाइनेन्स मिनिस्टर से किया जाना चाहिये।

श्री मधु लिमये : केन्द्रीय सरकार तो एक जंगल है। अगर उस में कोई फंस जाय तो पता ही नहीं चलता। कभी वित्त मंत्री, कभी उद्योग मंत्री और कभी किसी मंत्री, इस तरह टालमटोल चलती है।

Shri R. Barua: The definition of small-scale industries changes from time to time. May I know, what according to the Government should be the minimum and on what principles the conception of small-scale industry depends, whether it is on the capital invested or turnover every year or the profit made?

Shri F. A. Ahmed: Under the definition, the limit is Rs. 7½ lakhs.

श्री अब्दुल गनी डार : वजीर साहब, ने फरमाया कि वह छोटी इंडस्ट्रीज को तरक्की दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं या जो जो नई मशीनें आ रही हैं उन का गला काटने के लिये इन लाखों रुपयों के लेबल फारेन कन्ट्रीज से अपने यहां इमपोर्ट करने की इजाजत देते हैं? जो प्लैनिंग मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम 1500 करोड़ तक की मशीनें इम्पोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं, उन बड़ी मशीनों के आने से जो छोटी इंडस्ट्रीज है क्या उन की मार्केट तंग नहीं हो जायेगी? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार लेबल्स को क्यों इम्पोर्ट करती है और बड़ी मशीनों के आने से छोटी मशीनों को नुकसान पहुंचता है या नहीं?

وزیر صاحب نے فرمایا کہ چھوٹی انڈسٹریز کو ترقی دے رہے ہیں - میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے کہ چھوٹی انڈسٹریز جو ہیں یا جو نئی مشینیں آرہی ہیں - ان کا گلا کاٹنے کے لئے وہ لاکھوں روپیوں کے لیبل فارین کنٹریز سے اپنے یہاں امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں - جو پلاننگ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ۱۵۰۰ کروڑ تک کی مشینیں امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں - ان بڑی مشینوں کے آنے

ہے جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں کیا ان کی مارکیٹ تنگ نہیں ہو جائے گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار لیبلس کو کیوں امپورٹ کرتی ہے اور بڑی مشینوں کے آنے سے چھوٹی مشینوں کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں ؟]

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सवाल दूसरा है। जैसा मैंने कहा 47 ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं जिन को हम ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये रिजर्व कर दिया है। यहा बडी मशीनो और छोटी मशीनो के आने का सवाल नही है। उन से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का कोई नुकसान नही होना। अगर जरूरत हुई तो हम नम्बर को और भी बढा सकते हैं जिन मे इन के डेवेलपमेंट मे दिक्कत न हो। हम इन को पूरी मदद करने के लिये तैयार हैं।

श्री अब्दुल गनी डार : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। एक तरफ आप लेबल्स के लिये मशीनें बाहर से मगा रहे हैं, दूसरी तरफ लाखो रुपयो के लेबल आप बाहर से मगाने की इजाजत दे रहे हैं। यह दोनो चीजें आपस मे कैसे मुताबिकत रखती है ?

[میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ ایک طرف آپ لیبلس کے لئے مشینیں باہر سے منگا رہے ہیں۔ دوسری طرف لاکھوں روپیوں کے لیبلس آپ باہر سے منگانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے مطابقت رکھتی ہیں ؟]

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे इल्म में नहीं है कि बाहर से कोई लेबल यहां लाये जा रहे हैं जिन का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है।

श्री अब्दुल गनी डार : यह उन के इल्म मे क्यो नही है ? आखिर यहा ज्वायेंट रिस्पासिबिलिटी है। उन को हाउस को मिसलीड करने की इजाजत क्यो दी जा रही है ? लाखो रुपयो के लेबल इम्पोर्ट हो रहे हैं और यह कहते हैं कि उनके इल्म मे नही है। अगर उन के इल्म मे नही है तो वह इधर आयें और श्री मधु लिमये का उधर भेजिये। उन के इल्म मे हो जायेगा।

[یہ ان کے علم میں کیوں نہیں ہے۔ آخر یہاں جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ ان کو ہاؤس کو مسلیڈ کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے۔ لاکھوں روپیوں کے لیبل امپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو وہ ادھر آئیں اور شری مدھو لیمئے کو ادھر بھیجئے۔ ان کے علم میں ہو جائے گا۔]

Shri S. Kandappan: One of the greatest difficulties faced by the small scale industries sector is the non-availability of raw materials during scarcity times and high prices due to fluctuations in the market. To circumvent this difficulty, the Government was thinking of creating a reserve pool of raw materials to help the small scale industries when the materials are scarce in the market. May I know whether the Government has pursued that matter?

Shri F. A. Ahmed: We are trying to procure raw material for these small scale industries at as cheap a rate as possible and we are pursuing the various steps which we intend to take for the purpose of making it possible for these small scale industries people to get cheaper raw material.